

उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति- 2023

चर्चा में क्यों?

13 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड के चमोली ज़िले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति (उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति- 2023) को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखण्ड राज्य सौर ऊर्जा नीति- 2023 में सरकार ने यह अपेक्षा जताई है कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बजिली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से होगा। इनसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीणों की आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।
- नई सौर ऊर्जा नीति के तहत नजिी उपयोग या तीसरे पक्ष की बिक्री के लिये सरकारी या नजिी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएँ लगाई जा सकेंगी।
- यूपीसीएल के स्तर से राज्य के बाहर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएँ लगाई जा सकेंगी। यह प्रावधान इसलिये किया गया है क्योंकि यूपीसीएल को अपनी खरीदी जाने वाली बजिली का एक नश्चिति प्रतशित सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से खरीदना अनविर्य है।
- नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के लिये रोज़गार की भी गारंटी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतशित स्थानीय युवाओं को रोज़गार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा।
- पॉलिसी में यह प्रावधान भी किया गया है कि यूपीसीएल सौर ऊर्जा का एक ग्रीन टैरफि प्रस्ताव तैयार करेगा, जो कि नियामक आयोग को भेजा जाएगा। नियामक आयोग उपभोक्ताओं के लिये ग्रीन टैरफि चुनने का विकल्प दे सकता है।
- इसके अलावा पीक आवर्स में ग्रडि में सौर ऊर्जा देने वालों को फीड इन टैरफि से प्रोत्साहति कर सकता है। आसान पहुँच व नगिरानी के लिये वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) और ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम) का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- नई पॉलिसी में उरेडा की जमिंदारियाँ भी बढ़ाई गई हैं। इसके तहत उरेडा को एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना करनी होगी, जिसके तहत सगिल वडिों के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा। उरेडा को लैंडबैंक बनाना होगा तथा सभी सरकारी ज़मीनें और भवनों की सूची बनानी होगी, जहाँ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लग सकते हैं। इसी प्रकार, ऐसी नजिी भूमि भी चनिहति करनी होंगी, जनि पर कोई प्राइवेट व्यक्ती लीज पर अपना प्रोजेक्ट लगा सके।
- नई नीति से मिलने वाले फायदे-
 - सगिल वडिों पोर्टल के माध्यम से सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगेंगे।
 - लैंड यूज परविरतन शुल्क, न्यायालय शुल्क, पंजीकरण, भूमि उपयोग अनुमोदन, बाहरी वकिसा शुल्क, जाँच शुल्क और बुनयादी ढाँचा वकिसा शुल्क में छूट मिलेगी।
 - जो भी प्रोजेक्ट लगेगा, यूपीसीएल को अनविर्य तौर पर उससे बजिली खरीदनी होगी। इससे नविशकों का जोखमि कम होगा।
 - फीड इन टैरफि के माध्यम से अतरिकित्त बजिली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को मुआवज़ा मिलेगा। वहीं, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे वकिसा एवं स्वरोज़गार योजना को भी इससे लाभ पहुँचेगा।
 - अपने उपयोग के लिये और सामूहिक उपयोग के लिये नरिबाध अभगिम और एसजीएसटी व बजिली शुल्क में छूट मिलेगी।